सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कृषि-प्रधान जिले, श्रीगंगानगर में सहकारिता के आधार पर दो चीनी मिलें स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई योजना स्थगित कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अंशधारी-सदस्यों ने इन चीनी मिलों की स्थापना के लिये अपनी अंश-पूंजी भी राज्य सरकारों के पास जमा कर दी है और यदि हां, तो उन्होंने कुल कितनी राशि जमा की है; और

(ग) यदि, श्रीगंगानगर में चीनी मिलें स्थापित न करने का निर्णय किया गया है, तो सरकार अंशधारियों द्वारा जमा की गई अंश-पूंजी को वापस क्यों नहीं कर रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने के लाइसेंस के लिए कृषक सहकारी शुगर फैक्टरी लि०, गजसिंगपुर से एक प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार की सिफारिश के साथ प्राप्त हुआ था । केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों द्वारा मौके पर की गई जांच के उपरान्त उक्त प्रार्थना-पत्र मुख्य रूप से गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण नामंजूर कर दिया गया था ।

(ख) सदस्यों से 3.2 लाख रुपये इकट्ठे किये गये थे । यह राशि सहकारी समिति के खाते में जमा की गई थी न कि राज्य सरकार के पास ।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

Jayanti Shipping Company Establishment at Madras

2593. Shri Nambiar:
Shri Dinen Bhattacharya:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Jayanti Shipping Company's Establishments at Madras are being closed down after the taking over of management of Jayanti-Shipping Company;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of employees being retrenched; and

(d) the action taken to provide alternative employment?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (d). The services of all the employees of the Jayanti Shipping Company establishment at Madras have been dispensed with as a measure of economy. 20 employees are affected by this measure. It has not been possible to offer alternative employment to these persons.

Food Corporation of India

2594. Shri Priya Gupta: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the Four Regional Food Directorates and the Procurement Unit of Madhya Pradesh are being taken over by Food Corporation of India during 1966-67;

(b) whether a draft Food Corporation of India Amendment Bill envisaging the terms and conditions of transfer of existing Food Department employees was forwarded to the Employees' Association for their comments; and

(c) If so, under what authority the Constitutional safeguard provided under Article 311 of the Constitution to permanent employees and the decisions of the Supreme Court to that effect are being violated and ignored in the proposed draft the Food Corporation of India Amendment Bill and even against the guarantee given by the Minister of State for Food and Agriculture on 11th April, 1966 in this House?